

एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार के प्रयास

***सोम देव**

संक्षेप:-

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आर्थिक विकास का एक प्रमुख मौद्रिक स्रोत है। सस्ती मजदूरी और भारत के बदलते कारोबारी माहौल का लाभ लेने के लिए विदेशी कंपनियां तेजी से बढ़ते निजी शुभ व्यवसायों में सीधे निवेश करती हैं। 1991 के आर्थिक संकट के मद्देनजर भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ और तब से भारत में एफडीआई में लगातार वृद्धि हुई है, जिसने बाद में एक करोड़ (10 मिलियन) से अधिक नौकरियां पैदा कीं।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार, 17 अप्रैल 2020 को, भारत ने भारतीय कंपनियों को "वर्तमान COVID-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण" से बचाने के लिए अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में बदलाव किया। जबकि नई एफडीआई नीति बाजारों को प्रतिबंधित नहीं करती है, नीति यह सुनिश्चित करती है कि सभी एफडीआई अब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जांच के दायरे में होंगे।

परिचय:-

एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक देश में एक व्यवसाय में दूसरे देश में स्थित एक इकाई द्वारा नियंत्रित स्वामित्व के रूप में एक निवेश है। इस प्रकार प्रत्यक्ष नियंत्रण की धारणा द्वारा इसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग किया जाता है। मोटे तौर पर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में "विलय और अधिग्रहण, नई सुविधाओं का निर्माण, विदेशी परिचालन से अर्जित मुनाफे का पुनर्निवेश, और इंटर कंपनी ऋण" शामिल हैं। एफडीआई इक्विटी पूंजी, लंबी अवधि की पूंजी और अल्पकालिक पूंजी का योग है जैसा कि भुगतान संतुलन में दिखाया गया है। एफडीआई में आमतौर पर प्रबंधन, संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विशेषज्ञता में भागीदारी शामिल होती है। एफडीआई का स्टॉक किसी भी अवधि के लिए शुद्ध संचयी एफडीआई है। प्रत्यक्ष निवेश में शेयरों की खरीद के माध्यम से किया गया निवेश शामिल नहीं है (यदि उस खरीद के परिणामस्वरूप निवेशक

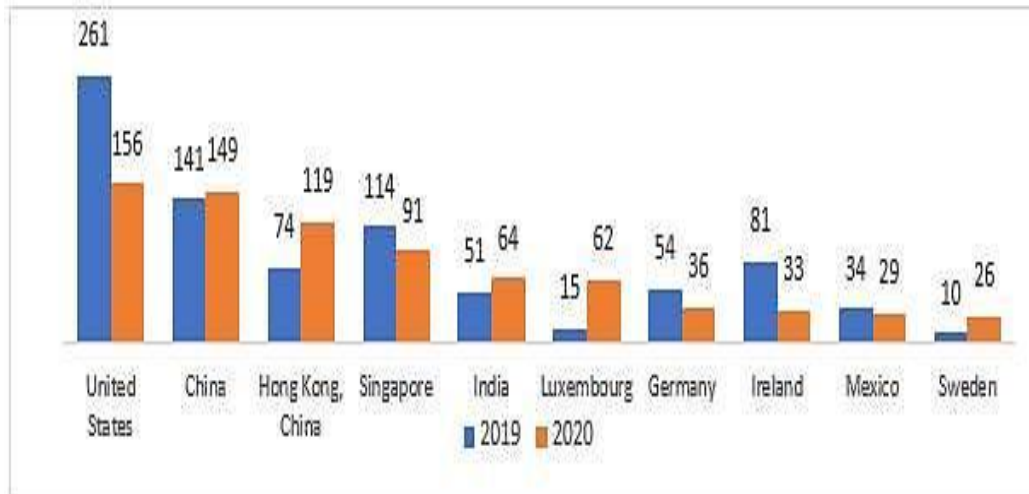
एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार के प्रयास

सोम देव

कंपनी के 10% से कम शेयरों को नियंत्रित करता है)।

भारतीय रिजर्व बैंक एफडीआई को एक गैर-सूचीबद्ध फर्म में किसी व्यक्ति या किसी विदेशी आधारित कंपनी (या किसी विदेशी निवेश) द्वारा सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी में 10% हिस्सेदारी की खरीद के रूप में परिभाषित करता है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के बाद से, भारत सरकार ने देश की निवेश नीतियों में ढील दी है और अनुकूल पहल की शुरुआत की है; इसलिए, भारत को विदेशी निवेशकों के लिए एक आदर्श निवेश केंद्र बनाने में सफलतापूर्वक रहा है। इसके बाद, अपेक्षाकृत कम वेतन, विशेष निवेश विशेषाधिकार जैसे कर छूट, एक अनुकूल कारोबारी माहौल और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता आधार जैसे कारक भी विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करते हैं। जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे भारत 2015 में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है।

शीर्ष 10 देशों का एफडीआई अंतर्वाह (अरब अमेरिकी डॉलर)



स्रोत: विश्व निवेश रिपोर्ट-2021

UNCTAD (व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) द्वारा जारी नवीनतम विश्व निवेश रिपोर्ट-2021 (WIR) के अनुसार, भारत को 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के पांचवें सबसे बड़े

एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार के प्रयास

सोम देव

प्राप्तकर्ता के रूप में स्थान दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और निर्माण क्षेत्रों में प्रमुख अधिग्रहण के कारण भारत के एफडीआई को बढ़ावा मिला। लार्सन एंड टुब्रो इंडिया के इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन डिवीजन की बिक्री 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में; ब्रुकफील्ड (कनाडा) और जीआईसी (सिंगापुर) द्वारा 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में टॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का अधिग्रहण; और यूनिलीवर इंडिया का ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर इंडिया (जीएसके यूके की एक सहायक कंपनी) के साथ 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर में विलय।

यह अध्याय भारत में एफडीआई के खराब प्रदर्शन के कारणों का अध्ययन करता है और इसे बढ़ाने के संभावित उपायों की जांच करता है। कई उभरते बाजार देशों के लिए पैनल डेटा का उपयोग करते हुए, अध्याय ने निष्कर्ष निकाला है कि एफडीआई को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक एफडीआई-विशिष्ट नीतियां नहीं हैं, बल्कि कॉर्पोरेट करों, व्यापार खुलेपन और अन्य व्यावसायिक जलवायु मुद्दों सहित व्यापक आर्थिक नीतियां हैं, जैसे कि नियामक गुणवत्ता और बोझ। यह अध्याय एफडीआई को आकर्षित करने में भारतीय राज्यों में मतभेदों को भी देखता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि व्यापक कारोबारी माहौल के मुद्दे बड़े पैमाने पर एफडीआई स्थान निर्धारित करते हैं।

साहित्य पुनरावलोकन:-

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) उभरते बाजार देशों द्वारा अन्य पूंजी प्रवाहों के पक्ष में है। एफडीआई ऋण सृजन नहीं है, पोर्टफोलियो प्रवाह की तुलना में कम अस्थिर है, और वित्तीय संकट के दौरान अपेक्षाकृत प्रतिरोधी है (अल्बुकर्क, 2003)। FDI को स्थानीय उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण के माध्यम से सकारात्मक स्पिलओवर के साथ भी जोड़ा गया है (ब्लॉमस्ट्रॉम और कोव्को, 2003), और इससे निर्यात प्रदर्शन और विकास में वृद्धि हो सकती है (बोरेन्ज़टीन और अन्य, 1998)। भारत में एफडीआई प्रवाह 1990 के दशक से बढ़ा है, लेकिन अन्य उभरते बाजार देशों की तुलना में कम है (सारणी 5.1)। 1990 के दशक की शुरुआत में समान परिमाण (जीडीपी के सापेक्ष) से शुरू होकर, चीन में एफडीआई ने उड़ान भरी, जबकि एफडीआई ने उड़ान भरी। भारत में घुस गया है। 2004 में भारत को सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.5 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जबकि चीन ने सकल घरेलू उत्पाद का 3.2 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया। डॉलर के संदर्भ में, चीन ने 2004 में भारत की तुलना में 16 गुना एफडीआई प्राप्त किया। साथ ही, निवेशक सर्वेक्षण एफडीआई के लिए एक गंतव्य के रूप में भारत में एक मजबूत रुचि की ओर इशारा करते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार के प्रयास

सोम देव

(अंकटाड) द्वारा निवेशक सर्वेक्षण और ए.टी. 2004 और 2005 में किर्नी ने भारत को FDI के लिए दूसरे सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थान दिया।

एफडीआई आकर्षित करने के लिए सरकार के प्रयास

1 फरवरी, 2017 को जारी किये गए बजट 2017-18 में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा कुछ उल्लेखनीय सुधारात्मक उपायों की घोषणा की गई है। इन सुधारों के अंतर्गत विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (Foreign Investment Promotion Board - FIPB) की समाप्ति, चुनावी प्रक्रिया के वित्त पोषण तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के क्षेत्र में लगने वाले कर की दरों में एकाएक 5% तक की कमी की गई है। हालाँकि, इन सभी उपायों के अलावा बजट में अत्यधिक ऋणग्रस्त कंपनियों (Over-Indebted Companies) की दोहरे तुलन-पत्र (Twin Balance Sheet) की समस्या तथा दबाव वाली परिसंपत्तियों (Stressed Assets) द्वारा बैंकिंग क्षेत्र को पंगु (hamstrung) बनाने संबंधी उपायों को अपनाने से परहेज़ भी किया गया है।

- विदित हो कि इस समय देश में तकरीबन 90% से भी अधिक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्ताव (Foreign Direct Investment Proposals) स्वचालित मार्ग (Automatic Route) के माध्यम से आते हैं।
- इन्हीं आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफडीआई के बढ़ते प्रवाह को नियमित एवं बाधामुक्त बनाने के लिये यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि अब विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाए।
- ध्यातव्य है कि विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड एक ऐसा निकाय है जिसके माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए तक के योजनागत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को मंजूरी प्रदान की जाती है।
- यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये अन्य उपायों की घोषणा करने पर भी विचार किया जा रहा है। संभवतः इन उपायों के अंतर्गत श्रम कानूनों में सुधार करने तथा डिजिटल भुगतानों की ओर झुकाव को बढ़ाने पर विशेष बल दिये जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।
- इस दिशा में कार्यवाही करते हुए भारत सरकार द्वारा अगले कुछ महीनों में ही विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के उन्मूलन हेतु एक रोडमैप जारी किये जाने संबंधी घोषणा किये जाने की सम्भावना है।

एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार के प्रयास

सोम देव

- दरअसल, शुरुआत के कई वर्षों तक भारत सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमोदन के ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भारत में आने की अनुमति प्रदान की गई थी। ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के अप्रैल-सितम्बर माह के दौरान देश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तकरीबन 30% (21.62 बिलियन डॉलर) की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व्यवस्था

- रेटिंग एजेंसी मूडीज़ द्वारा बजट 2017-18 के संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया इस वर्ष का बजट आर्थिक दृष्टि से न केवल एक विवेकपूर्ण बजट है, बल्कि यह एफडीआई के स्तर में वृद्धि करने हेतु उठाए गए कदमों को स्थिरता प्रदान करने के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास को भी आधार प्रदान करने का कार्य करेगा।
- ध्यातव्य है कि डिजिटल भुगतानों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक लेन-देनों के लिये उपयोग की जाने वाली विभिन्न मशीनों पर शुल्क की समाप्ति, आधार आधारित भुगतान व्यवस्था का आरम्भ करने, भुगतान अवसंरचना को मज़बूती प्रदान करने तथा अन्य उपायों के साथ-साथ भुगतान संबंधी शिकायतों के निपटान हेतु एक प्रभावकारी तंत्र की स्थापना करने का भी प्रस्ताव जारी किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा श्रम कानूनों को चार श्रेणियों- मज़दूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण एवं सुरक्षा तथा काम करने की स्थिति के रूप में सरलीकृत किया जाएगा। राज्य के स्वामित्व वाली उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या से जूझ रहे बैंकों को पूंजी समर्थन प्रदान करने की आशा के विपरीत, वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बैंकों की स्थिति में सुधार करने के लिये मौजूदा इंद्रधनुष योजना (Indradhanush plan) पर ही भरोसा व्यक्त किया गया है।
- बैंकों के पुनर्पूँजीकरण (Recapitalisation) के लिये आवंटित की जाने वाली इस 10,000 करोड़ रुपए की निरर्थक धनराशि (Piffiling Amount) से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अभी भी इस समस्या के केंद्र में नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि बैंकों को इस समस्या से बाहर निकालने हेतु आवश्यक पूंजी की तुलना में यह एक बहुत ही तुच्छ आवंटन है।

एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार के प्रयास

सोम देव

- हालाँकि, खराब ऋणों की समस्या से निपटने के लिये सरकार द्वारा एक नए कानून की स्थापना के संबंध में विचार किया जा रहा है ताकि ऋण न चुकाने वाले लोगों की सम्पत्ति को ज़ब्त किया जा सके।
- सरकार द्वारा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies) द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूति रसीदों की सूचियाँ तैयार करने तथा व्यापार करने संबंधी अनुमति प्रदान की जाएगी ताकि गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने में सहायता प्राप्त हो सके।

अंतर्राष्ट्रीय मानक.3 1991 से पहले सभी एफडीआई प्रस्तावों पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता था, जिसमें एफडीआई कुल इक्विटी निवेश का 40 प्रतिशत था। 1991 में, 34 क्षेत्रों में 51 प्रतिशत तक स्वामित्व की स्वतः स्वीकृति की अनुमति देने के लिए नीति में संशोधन किया गया था। 1997 में 111 क्षेत्रों को कवर करने के लिए इस सूची का विस्तार किया गया था। 2000 में, नीति को "नकारात्मक सूची" दृष्टिकोण का उपयोग करके एक में बदल दिया गया था। तब से, अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है, इस आवश्यकता के साथ कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 30 दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाए। इस सामान्य नीति के महत्वपूर्ण अपवाद हैं जिनके लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी जाती है। इन अपवादों में लाइसेंस के अधीन उद्योग, कुछ शर्तों के तहत मौजूदा भारतीय कंपनी का अधिग्रहण, उद्योग जहां विदेशी निवेशक की उसी क्षेत्र में उपस्थिति है, और उद्योग जहां क्षेत्रीय नीतियां लागू होती हैं (तालिका 5.2)। खुदरा व्यापार, लॉटरी व्यवसाय, जुआ और सट्टेबाजी, परमाणु ऊर्जा और कृषि और वृक्षारोपण में FDI की अनुमति नहीं है। एफडीआई के लिए भारत की नियामक व्यवस्था को 1991 से धीरे-धीरे उदार बनाया गया है, और इसके परिणामस्वरूप, शासन अब विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानक.3 1991 से पहले सभी एफडीआई प्रस्तावों पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता था, जिसमें एफडीआई कुल इक्विटी निवेश का 40 प्रतिशत था। 1991 में, 34 क्षेत्रों में 51 प्रतिशत तक स्वामित्व की स्वतः स्वीकृति की अनुमति देने के लिए नीति में संशोधन किया गया था। 1997 में 111 क्षेत्रों को कवर करने के लिए इस सूची का विस्तार किया गया था। 2000 में, नीति को "नकारात्मक सूची" दृष्टिकोण का उपयोग करके एक में बदल दिया गया था। तब से, अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है, इस आवश्यकता के साथ कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 30 दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाए। इस सामान्य नीति के महत्वपूर्ण अपवाद हैं जिनके लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी

एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार के प्रयास

सोम देव

निवेश की मंजूरी दी जाती है। इन अपवादों में लाइसेंस के अधीन उद्योग, कुछ शर्तों के तहत मौजूदा भारतीय कंपनी का अधिग्रहण, 4 उद्योग जहां विदेशी निवेशक की उसी क्षेत्र में उपस्थिति है, और उद्योग जहां क्षेत्रीय नीतियां लागू होती हैं (तालिका 5.2)। खुदरा व्यापार, लॉटरी व्यवसाय, जुआ और सट्टेबाजी, परमाणु ऊर्जा और कृषि और वृक्षारोपण में FDI की अनुमति नहीं है।

निष्कर्ष

भारत में एफडीआई को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक एफडीआई विशिष्ट नीतियां नहीं हैं, बल्कि कॉरपोरेट कर, व्यापार खुलापन और अन्य व्यावसायिक जलवायु मुद्दों जैसे नियामक गुणवत्ता और बोझ सहित व्यापक आर्थिक नीतियां हैं। भारत ने अपनी एफडीआई व्यवस्था को उदार बनाने में काफी प्रगति की है, जो महत्वपूर्ण एफडीआई प्रवाह को आकर्षित करने के लिए एक आवश्यक लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। एफडीआई को आकर्षित करने में भारतीय राज्यों में मतभेद एफडीआई-विशिष्ट प्रोत्साहनों के बजाय एफडीआई निर्धारित करने में व्यापार माहौल के महत्व को और रेखांकित करते हैं। एफडीआई के लिए भारत की जबरदस्त क्षमता पर वर्तमान अंतरराष्ट्रीय ध्यान के साथ, एफडीआई प्रवाह में भारी वृद्धि करने के लिए संरचनात्मक सुधारों पर तेजी से प्रगति के लिए यह एक उपयुक्त समय होगा।

***शोधार्थी**

**राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय
अलवर, राजस्थान**

संदर्भ

1. Albuquerque, Rui, 2003, "The Composition of International Capital Flows: Risk Sharing Through Foreign Direct Investment," *Journal of International Economics*, Vol. 61 (December), pp. 353–83.
2. A.T. Kearney, 2004 and 2005, "FDI Confidence Index" (Alexandria, Virginia: Global Business Policy Council).
3. Bajpai, Nirupam, and Jeffrey D.Sachs, 2000, "Foreign Direct Investment in India," *Development Discussion Paper No.759* (Cambridge, Massachusetts: Harvard Institute for International Development).
4. Blomström, Magnus, and Ari Kokko, 2003, "The Economics of Foreign Direct Investment Incentives," *NBER Working Paper No. 9489* (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research).

एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार के प्रयास

सोम देव

5. Borensztein, Eduardo, Jose De Gregorio, and Jong-Wha Lee, 1998, "How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?" *Journal of International Economics*, Vol. 45, Issue 1, pp. 115–35.
6. Botero, Juan, Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, 2003, "The Regulation of Labor," NBER Working Paper No. 9756 (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research).
7. Chang, Ching-huei, and Peter W.H. Cheng, 1992, "Tax Policy and Foreign Direct Investment in Taiwan," in *The Political Economy of Tax Reform*, ed. by Takatoshi Ito and Anne O. Krueger (Chicago: University of Chicago Press).
8. Confederation of Indian Industry and World Bank, 2002, *Competitiveness of Indian Manufacturing: Results from a Firm-Level Survey* (New Delhi).